क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 296, सोमवार, 26 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने की सरकार की तारीफ

लखनऊ, एजेंसी। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने कि सुरक्षा प्रबन्धों पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य की सरकारों को धन्यवाद दिया। अयोध्या में हो रहे आयोजन पर अंसारी ने कहा कि साधु-संत भले लोग। आयोजन सरकार की निगरानी में हो रहा। सरकार सब देख रही है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी के अयोध्या छोड़ने की धमकी के बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई। सुरक्षा बढ़ाई जाने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि वह सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों से संतुष्ट हैं। उन्होंने अयोध्या में सुरक्षा बंदोबस्त करने के लिये सरकार की तारीफ की।

नेता के भाई की गला दबा हत्या, स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद

गोरखपुर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालस छात्रसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष बंधू उपेन्द्र सिंह के छोटे भाई उद्यान निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह उर्फ संजय सिंह की शनिवार की सुबह गला दबाकर हत्या कर दी गई। सत्येंद्र सिंह अपने भाई बंधू सिंह से मिलने मोहद्दीपुर के श्रीरामपुरम स्थित उनके किराए के कमरे पर गए थे। स्कूटी खड़ी करने के विवाद में बगल के एक दम्पति और उनके दो बेटों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित हउली गांव निवासी सत्येन्द्र कुमार सिंह गोरखपुर उद्यान विभाग में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। वे मंडलायुक्त कार्यालय के समीप स्थित ट्रांजिट हास्टल में परिवार के साथ रहते थे। उनके बड़े भाई भाजपा नेता बंधू उपेंद्रनाथ सिंह मोहद्दीपुर के श्रीरामपुरम कालोनी में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। बंधू सिंह लम्बे समय बाद शुक्रवार की देर रात कमरे पर लौटे थे। शनिवार की सुबह 9:30 बजे सत्येन्द्र सिंह स्कूटी पर पत्नी संगीता को बैठाकर बड़े भाई के कमरे पर पहुंचे। उन्होंने स्कूटी सड़क के किनारे मकान से सटाकर खड़ी कर दी और पत्नी के साथ भाई के कमरे पर चले गए। पड़ोस में रहने वाले उमेश चंद्र जायसवाल का बेटा शशांक और सनी वहां पहुंचा और स्कूटी खड़ी देकर गालियां देने लगा। शशांक गालियां दे रहा था कि उसी समय सत्येंद्र सिंह भाई के कमरे से निकलकर नीचे आ गए। उन्होंने शशांक को टोका तो उसने अपने भाई अभिजीत और परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया। मनबढ़ों ने उनका गला कस दिया। सत्येंद्र सिंह चिल्लाए। आवाज सुनकर बंधू और उनके साथ कुछ और लोग दौड़कर पहुंचे लेकिन तब तक सत्येंद्र सिंह बेहोश होकर गिर चुके थे। बंधू और उनके साथ के लोग सत्येंद्र सिंह को लेकर छात्रसंघ चौराहे पर स्थित एक अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टरों ने सत्येंद्र सिंह को देखने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस तत्काल हरकत में आई

भाजपा नेता के भाई की हत्या की खबर मिलते ही कैंट थाने की पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। कैंट इंस्पेक्टर रवि राय ने अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर उमेश चंद्र जायसवाल, उसकी पत्नी तथा बेटों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी विनय सिंह और सीओ कैंट प्रभात राय भी तत्काल अस्पताल पहुंच गए।

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

बंधू उपेन्द्र नाथ सिंह की तहरीर पर पुलिस ने उमेश चंद्र जायसवाल, उसकी पत्नी संध्या, पुत्र शंशाक जायसवाल उर्फ सनी व अभिजीत जायसवाल के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

सत्येंद्र के सबसे बड़े भाई हैं दरभंगा जिला जज

सत्येन्द्र उर्फ संजय सिंह अपने भाइयों में छठे नम्बर पर थे।

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक रोहतांग पास पर भारी बर्फ जम गई, जिसे वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए शुक्रवार को कटर मशीन से हटाया गया।

>>> सीने में लगी थीं 4 गोलियां

26/11 हमले में घायल इस मरीन कमांडो को बूढ़ी महिला से मिला दौड़ने का जज्बा,

बुलंदशहर, एजेंसी। मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले वीभत्स मंजर आज भी लोगों के जेहन में कैद है। यहां आतंकियों से लोहा लेते हुए बुलंदशहर के जांबाज जवान और बहादुर मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने अपने सीने में कई गोलियां खाई थीं, किस्मत से उनकी जान बच गई। लेकिन अभी भी उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। अब दुर्गम लद्दाख में आयोजित मैराथन दौड़ में अपनी ताकत दिखाएंगे। बता दें कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गोलियों ने उनके फेफड़े भेद दिए थे। कई ऑपरेशन हुए और नौ साल इलाज चला, मगर उन्होंने हौसला नहीं खोया। उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले स्थित भटौना गांव के रहने वाले तेवतिया 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के समय मरीन ड्राइवर थे। कमांडो ऑपरेशन करने वाली दूसरी टीम में शामिल होकर वह होटल पहुंचे थे। घुप्प अंधेरे कमरे में तीन आतंकी छिपे थे। जान की परवाह न करते हुए वह कमरे में घुस गए। आतंकवादियों ने प्रवीण तेवतिया पर गोलियां बरसा दीं। एक गोली सीने से आर-पार हो गई, लेकिन घायल होने के बावजूद प्रवीण तेवतिया हार नहीं मानी और तीन आतंकियों को ढेर कर दिया।

वीरता को सम्मान

प्रवीण तेवतिया की वीरता से अनुग्रहीत देश ने भी अपने लाल को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने प्रवीण तेवतिया को शांतिकाल के शीर्ष वीरता पदकों में शामिल शौर्य चक्र से सम्मानित किया।

बूढ़ी महिला बनी प्रेरणा

प्रवीण ने बताया कि 2012 में मुंबई में उन्होंने 64 वर्षीय बूढ़ी महिला को दौड़ते हुए देखा, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली। इसके बाद वह पैदल और फिर दौड़ना शुरू किया। 2015 में हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। पांच साल की कड़ी मेहनत से वह खुद को राष्ट्रीय धावक बने।

जज्बा कमजोर फेफड़ों पर हावी-

तेवतिया को लगी गोली से उनका फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे।

50 हजार रुपये में आठवीं फेल 67 बच्चों को कराया हाईस्कूल

बरेली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के बरेली में जवाहर मीना इंटर कॉलेज ने आठवीं फेल 67 विद्यार्थियों से 50-50 हजार रुपये लेकर एक ही वर्ष में उन्हें हाईस्कूल पास करवा दिया। इन छात्रों को कक्षा नौ में जवाहर मीना इंटर कालेज ठिरिया में प्रवेश दिलाया गया। उसी वर्ष हाईस्कूल में जनक कुमारी स्कूल जौनपुर में भी एडमिशन करा दिया। स्कूल को कुछ छात्रों ने जब पूरे पैसे नहीं दिए तो उनकी मार्कशीट रोक दी गई। इसके बाद मामला खुला। इस गोलमाल की शिकायत उच्चाधिकारियों के पास पहुंची तो हड़कंप मच गया। ठिरिया निवासी अनवार अली खां, शमशाद, अरबाज ने तमाम साक्ष्यों के साथ जेडी और डीआईओएस से जवाहर मीना इंटर कालेज की शिकायत की।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जवाहर मीना के प्रबंधक विपिन जायसवाल ने कक्षा आठ की फर्जी मार्कशीट के आधार पर कक्षा 9 में 67 एडमिशन किये। इनका उसी वर्ष साठगांठ कर जनक कुमारी हायर सेंकेंड्री स्कूल जौनपुर में हाईस्कूल में प्रवेश करवा दिया गया। इस तरह से मात्र एक वर्ष में ही विद्यार्थियों को हाईस्कूल पास करवा दिया गया। तमाम छात्र तो परीक्षा देने भी नहीं गए। इन छात्रों का केंद्र रामदुलार इंटर कालेज अहमदपुर जौनपुर में पड़ा था। इसमें बड़ी संख्या में ऐसी मार्कशीटें हैं जिनमें पैसे बकाया होने की पर्ची लगी है। छात्रों पर पांच हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक बकाया होने की बात कही जा रही है।

वर्ष 2016 की है मार्कशीट

छात्रों से इस गोलमाल के लिए 50-50 हजार रुपये लिए गए थे। जिन छात्रों ने समय पर पैसे दे दिए,उनको स्कूल ने मार्कशीट भी दे दी। जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनकी मार्कशीट रोक ली गई। सुबूत के तौर पर जो मार्कशीट भेजी गई हैं, वो वर्ष 2016 की हैं।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके पास वर्ष 2018 की परीक्षा के संबंध में हुई बड़ी गड़बड़ी के भी पुख्ता सुबूत हैं। इसका खुलासा भी वो जल्द करेंगे।

नॉमिनल रोल दे रहीं गोलमाल की गवाही

पूरे मामले की गवाही यूपी बोर्ड की तरफ से जारी नॉमिनल रोल दे रहे हैं। नॉमिनल रोल में छात्र का नाम, उसके माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय आदि लिखे होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने दो नॉमिनल रोल उपलब्ध कराए हैं। एक नॉमिनल रोल जवाहर मीना स्कूल का है तो दूसरा जनक कुमारी जौनपुर का।

जन्म तिथि में बदलाव कर किया खेल

जवाहर मीना के छात्रों को जब उसी वर्ष जनक कुमारी में प्रवेश दिलाया गया तो उनकी उम्र बदल दी गई। उदाहरण के तौर पर अभिषेक की उम्र जवाहर में 25 सितम्बर 2002 है। जबकि जनक कुमारी में उसी वर्ष उम्र 25 सितंबर 2001 है।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। बिम्सटेक देशों में आतंकवाद, मानव तस्करी और ड्रग्स स्मगलिंग की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के मुख्य न्यायाधीशों से सीधी बात करेंगे।

यह बातचीत 26 नवंबर को होने वाले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में होगी।

यह पहला मौका होगा जब कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठक करेंगे।

बिम्सटेक (बे ऑफ बेंगाल इनीशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल, टेक्नीकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन) देशों के न्यायाधीशों का यह पहला सम्मेलन है जो भारत में किया जा रहा है। उपरजिस्ट्रार राकेश शर्मा ने बताया कि यह सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट परिसर में होगा।

इसमें बांग्लादेश और म्यांमार के मुख्य न्यायाधीश तथा नेपाल, थाईलैंड और भूटान के वरिष्ठ जज भाग लेंगे। सम्मेलन में इन देशों की भूमि से होने वाली मानव तस्करी, आतंकवाद और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी की रोकथाम के कानूनों के अमल पर बातचीत होगी। सूत्रों के अनुसार रविवार को इस क्लोजडोर कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका होगा जब कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री न्यायपालिका के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठक करेंगे।

सीधी मुलाकात नहीं होती

राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के अलावा प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश से कभी सीधे नहीं मिलते और सुप्रीम कोर्ट में तो यह कभी नहीं हुआ है।

कोई बात करनी होती है तो दोनों में पत्र व्यवहार होता है, मुलाकात नहीं। वहीं मुख्य न्यायाधीश से केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कानून मंत्री मिलते हैं, क्योंकि कानून मंत्रालय न्यायपालिका का प्रशासिनक मंत्रालय है।

फैसले अगले दिन सार्वजनिक होंगे

इस कार्यक्रम में लिए फैसलों के बारे में अगले दिन सोमवार को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में सार्वजनिक किया जाएगा। यह बैठक लड़ाकू विमान राफेल की डील तथा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख को छुट्टी पर भेजने के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की पृष्ठभूमि में होगी। इन केसों में एनडीए सरकार की साख दांव पर है।

बच्चों को बताएंगे उत्पीड़न से बचने के तरीके, सरकार चलाएगी अभियान

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आपका बच्चा उदास रहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, उसे आसपास के वातावरण से डर लगता है तो यह खतरनाक संकेत है। ऐसे बच्चों की तुरंत काउंसलिंग होनी चाहिए और उनके इन लक्षणों की वजह तलाशनी चाहिए। सुरक्षित पड़ोस के तहत अब सरकार बच्चों को प्रशिक्षण देकर बताएगी कि उत्पीड़न को कैसे पहचाने। माना जाता है कि कई बार बच्चे अपने साथ होने वाले उत्पीड़न को समझ नहीं पाते और वे उसे अपने से बड़ों के सामने बता भी नहीं पाते। ऐसे में कई बार बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। महिला व बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि बच्चों के खतरनाक संकेतों को पढ़ने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी

उन्होंने कहा कि बच्चों के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का दायरा बढ़ रहा है। एक साल में एक करोड़ से ज्यादा शिकायतें चाइल्ड लाइन पर दर्ज हुई हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार इससे निपटने और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने वाली है।

सुरक्षा से ज्यादा बचाव जरूरी है

श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षित पड़ोस (सेफ नेबरहुड प्रोजेक्ट) को देश भर में आगे बढ़ाएगी। बच्चों के उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों से इसे प्राथमिकता से लेने को कहा है। राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का मानना है सुरक्षा से ज्यादा बचाव जरूरी है।

दिल्ली में 'हौसला' कार्यक्रम आयोजित होगा

महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने बताया कि बच्चों के आसपास ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस साल चाइल्ड सेफ्टी थीम के साथ 26 से 29 नवंबर तक हौसला कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर के बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे हिस्सा लेंगे।

बढ़ रही शिकायत

चाइल्ड लाइन के जरिए बच्चे बड़ी संख्या में अपने ऊपर उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं

- वर्ष 2017-18 में 1.34 करोड़ बच्चों से जुड़ी शिकायतें चाइल्ड लाइन में दर्ज कराई गई
- 2.28 लाख बच्चों से जुड़ी शिकायतों के मामलों में एजेंसियों ने सीधा दखल दिया है

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव: आखिरी समय का चुनाव प्रबंधन निर्णायक होगा

बच्चों को यह बताएंगे

सुरक्षित पड़ोस के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डिबेट, ड्राइंग सहित प्रोजेक्ट से जागरुक बनाया जाएगा। उन्हें घटनाओं की सूचना पर भी अलर्ट किया जाएगा।

राज्य भी शामिल होंगे

सचिव ने कहा कि हमने सुरक्षित पड़ोस योजना का साफ्ट लांच अक्तूबर में किया लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर करने की जरूरत है। पूरे देश में राज्यों की मदद से अभियान चलाया जाएगा।

शर्मनाक स्थिति

- देश में हर पल कोई न कोई बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार होता है
- इनमें से ज्यादातर मामलों की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती
- 50 फीसदी यौन उत्पीड़न करने वाले लोग बच्चों को पहले से जानते हैं

>>> डीयू में हेफा का विरोध, केवीएस हेफा लोन लेने की तैयारी में

विविद्यालयों के बाद अब स्कूलों को भी हेफा देने की तैयारी

नई दिल्ली एजेंसी। दिल्ली विविद्यालय में जहां हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग (हेफ) का विरोध हो रहा है। वहीं अब स्कूलों को हेफा दिये जाने की तैयारी है। इस मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने हेफा से लोन लेने का प्रस्ताव किया है। साथ ही संगठन ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी बात की है। बताया जाता है कि मंत्रालय हेफा में स्कूलों को भी शामिल करने की प्रक्रिया में हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कई स्कूलों के निर्माण अन्य कायरे के लिए 1032.50 करोड़ रपए का प्रस्ताव तैयार किया है। केन्द्रीय विद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में हेफा से लोन लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में 50 नए स्कूलों की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी। इनके निर्माण के लिए हेफा को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

इन स्कूलों के निर्माण के लिए 911.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसी प्रकार तीन सालों में क्रमश: 300 करोड़ 2018-19, 300 करोड़ रपए 2019-20 और 311.50 करोड़ रपए 2020-21 में जरुरत होगी। इस प्रकार चल रही 11 परियोजनाओं के लिए 121 करोड़ रपए की जरुरत होगी। इस प्रकार कुल 1032. 50 करोड़ रपए के लोन की जरूरत है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उम्मीद है यह लोन जून 2018 से मार्च 2021 के वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए मिल सकेगी।

सूत्रों के अनुसार अभीं केन्द्रीय विद्यालय को हेफा के तहत लोन नहीं मिला है। हालाकि संगठन ने प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को भेजा हुआ है। डीयू कार्यकारी परिषद सदस्य डॉ एके भागी ने बताया कि हेफा से लोन लेने का विविद्यालयों में विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं कि विविद्यालयों को सीधे सरकार अनुदान दे न कि कोई एजेंसी। उन्होने कहा कि यदि हेफा से लोन लेते हैं तो ऐसे में विविद्यालयो में इस कर्ज को चुकाने के लिए फीस में इजाफा होने की स्थिति बन सकती है।

दखल

आतंकी हमला बड़ी साजिश का अंग

निरंकारी मिशन के सत्संग पर हमले के बाद यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि पंजाब को ठीक 1980 के दशक के भयावह दौर में ले जाने की साजिशें रची जा चुकी हैं। हमले का स्थान और समय बताता है कि यह बिल्कुल सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार पंजाब और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियोंके साथ खुफिया एजेंसियों की बैठक बुलाकर पूरी स्थिति का आकलन करे तथा सुरक्षा ऑपरेशन की योजना बनाए।

देश के जिन लोगों ने 1980 के दशक में पंजाब के भयावह आतंकवाद के दृश्य देखे हैं उनका दिल निश्चय ही अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र के अदलीवाल गांव के निरंकारी भवन पर हुए हमले से दहल गया होगा। इसे आतंकवादी हमले के अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई एक व्यक्ति निशाने पर होता तो हमले को दूसरे नजरिए से देखा जा सकता था। यहां पूरा समूह निशाने पर था। रविवार को निरंकारी भवनों में अनुयायी एकत्रित होते हैं और सत्संग चलता है। सत्संग के बीच बाइक सवार तीन युवक आएं और बम चलाकर भाग जाएं तो साफ है कि वो निश्चित उद्देश्य के तहत निरंकारी लोगों की हत्या करना चाहते थे। इस घटना में कम लोगों की जान गई और घायल होने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी इस आधार पर इसकी भयावहता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे ही बाइकों पर नकाबपोश के रूप में आकर हमले करते थे। इसलिए यह तरीका भी भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। पंजाब पुलिस अपने बचाव में जो भी तर्क दे लेकिन यह स्थान अमृतसर शहर से केवल सात किलोमीटर दूर है। अमृतसर स्टेशन से इसकी दूरी 13.7 किलोमीटर तथा पाक सीमा से 17-18 किलोमीटर है। इसलिए इसे दूरस्थ गांव नहीं माना जा सकता।

पंजाब पुलिस का अधिकृत बयान है कि उनके पास इस संभावित खतरे को लेकर कोई इनपुट नहीं था। निरंकारी समाज को लेकर किसी भी तरह का मुद्दा नहीं था और न ही ऐसा कोई इनपुट पुलिस के पास था। यह बयान स्वीकार्य नहीं है। क्या पुलिस के पास ऐसी सूचना होगी कि फलां संस्थान और फलां जगह हमला होगा तभी उसे सटीक इनपुट माना जाएगा? धार्मिक स्थलों पर हमले का इनपुट तो था। कुछ ही दिनों पहले थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पंजाब में आतंकवादी शक्तियां फिर सिर उठा रही हैं और तुरत कार्रवाई नहीं की गई तो कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। सेना प्रमुख बिना पुष्ट सूचना के इतनी बड़ी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते। जाहिर है, पंजाब पुलिस ज्ञात तथ्य को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमले के तीन दिनों पहले खबर आई थी कि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इनपुट भेजा है कि कश्मीर का खूंखार आतंकी जाकिर मूसा अपने साथियों के साथ पंजाब के रास्ते दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पनाह ले सकता है। इनपुट में कहा गया था कि जैश-ए-मोहम्मद के छह-सात आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे हैं। सीमा पार से छह-सात आतंकवादियों के पंजाब में घुसने की खबर भी थी। जाकिर मूसा के अमृतसर में देखे जाने की खबर आई थी। पंजाब से अचानक उसकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी।

खुफिया ब्यूरो को इनपुट मिला था कि जाकिर मूसा गिरोह के सात आतंकी फिरोजपुर आए थे। पठानकोट जिले के माधोपुर के नजदीक ड्राइवर की हत्या कर एसयूवी कार छीनने वाले चार लोग अभी तक फरार हैं। पंजाब पुलिस ने ही बताया था कि ये चार आतंकवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पंजाब में घुसे हैं। ये चारों संदिग्ध जम्मू रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आए थे। दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियों ने पांच संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मेल की गई थीं। इन सब सूचनाओं के बाद ही पिछले कई दिनों से पंजाब में हाईअलर्ट था। पिछले दिनों जालंधर से शबनमदीप सिंह नामक खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था। इसने पाकिस्तान की साजिशों के बारे में बताते हुए कहा था कि दीपावली से पूर्व हमले की योजना है। इसके बाद आखिर पुलिस को क्या इनपुट चाहिए था? जालंधर में ही एक कश्मरी युवक ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ पंजाब पुलिस ने हाल ही में पंजाब के संस्थानों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के दो गिरोहों का पर्दाफाश किया था, जिनके संबंध कश्मीरी आतंकी संगठनों से थे। जिन आतंकवादियों के पाकिस्तान से पंजाब में सड़क मार्ग से फिरोजपुर में घुसने की आशंका थी उनकी तलाशी अभियान चल रहा था।

यह खबर भी लंबे समय से थी कि लंदन से कनाडा तक के खलिस्तान समर्थक पंजाब में फिर से हिंसा और अशांति की स्थिति पैदा करने के लिए सक्रिय हैं तथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने स्तर पर काम कर रही है। 18 महीनों में स्वयं पंजाब पुलिस ने 15 से ज्यादा आतंकवादी मॉड्यूल को नष्ट करने का दावा किया है। अगर आपने 15 मॉड्यल पकड़े तो निश्चय ही ऐसे अनेक मॉड्यूल छिपे हुए होगे। आतंकियों ने तो बयान जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एवं सेना प्रमुख जनरल रावत को जान से मारने की धमकी दे रखी है। इन सबके बाद कैसा इनपुट चाहिए यह समझ से परे है। 12 अगस्त को लंदन के सिख्ख फार जस्टिस के बैनर से 2020 सिख्ख जनमत संग्रह रैली निकाली गई। इसमें खालिस्तानी उग्रवादी समूहों के बचे आतंकवादियों को संदेश निहित था कि आप सक्रिय हो, आपके साथ बड़ा समुदाय खड़ा है। यह अलग बात है कि इनसे बड़ी संख्या में सिखों ने ही लंदन में विरोध में रैली निकालकर करारा जवाब दे दिया। किंतु इससे इन दुष्ट समूहों की सक्रियता का पता तो चल गया। इसलिए ऐसे हमले की आशंका नहीं होने के किसी बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत विरोधी खालिस्तानी समूह भाड़े के हत्यारों से बीच-बीच में अलग-अलग संगठनों की हत्याएं करवा रहे थे। आरएसएस के नेताओं की हत्या का उद्देश्य यह था कि इससे हिंदू गुस्से में सिखों से लड़ें और प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ जाए। ठीक यही दृष्टिकोण निरंकारी अनुयायियों पर हुए हमले में भी देखा जा सकता है। बाबा बूटा सिंह द्वारा 1929 में स्थापित निरंकारी मिशन के दुनिया में एक करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। पंजाब के तरनतारन, गुरदासपुर, मोगा, लुधियाना, पठानकोट सहित अनके स्थानों पर निरंकारी अनुयायियों की बड़ी संख्या है। ठीक सत्संग के समय हमला करने का सीधा उद्देश्य यही हो सकता है कि ये गुस्से में हिंसा आरंभ कर दें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 40 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 1978 को वैसाखी के दिन अमृतसर में निरंकारी भवन पर हुए हमले के बाद पंजाब हिंसा की चपेट में आ गया था और भिंडरावाले वहीं से एक वर्ग में लोकप्रिय हुआ। हमले के बाद अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए थे। इसके विरोध में रोष दिवस मनाया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इसको उग्र रूप दिया और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं।

पंजाब के आतंकवाद पर काम करने वाले कई विद्वान मानते हैं कि अगर वह हमला न हुआ होता तो भिंडरावाले और उसके साथी एक वर्ग के हीरो बनकर नहीं उभरते एवं उस प्रकार के भयावह चरमपंथ का आविर्भाव नहीं होता। तो पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने के हाल के वर्षों के सारे प्रयासों, आतंकियों से संबंधित इनपुट, गिरफ्तारियां, आतंकवादी मॉड्यूल को विफल करने तथा अंततः निरंकारी मिशन के सत्संग पर हमले के बाद यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि पंजाब को ठीक 1980 के दशक के भयावह दौर में ले जाने की साजिशें रची जा चुकी हैं। हमले का स्थान और समय बताता है कि यह बिल्कुल सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।

अवधेश कुमार
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

अब बदलनी होगी बाल गृहों की छवि

बिहार व उत्तरप्रदेश के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने देशभर के 539 बाल गृहों को बंद कर दिया है। ये सभी गृह अनियमित तरीके से चलाए जा रहे थे। सवाल है कि प्रशासनिक मशीनरी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने में विमुख क्यों हो जाती है?

बिहार में यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामलों के उजागर होने की पृष्ठभूमि में देशभर के बालगृहों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर में कुल 539 बाल गृहों (सीसीआई) को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में 377 बालगृहों को बंद किया गया, जो सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों में सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 78 और तेलंगाना में 32 बालगृह बंद कर दिए गए हैं। बिहार के एक आश्रय गृह में 34 नाबालिग बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आने के बाद मंत्रालय ने अगस्त में राज्यों को अपने सभी बालगृहों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया था कि करीब 539 बालगृह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या पंजीकृत नहीं हैं। सरकार ने भले ही 539 बाल गृहों को बंद कर बच्चों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध करा दिया है, मगर क्या जिला प्रशासन के अफसरों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए। जिन जिलों में इस तरह के बाल आश्रय गृह संचालित हो रहे थे, वहां के अफसरों ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया।

देशभर में दो तरह के बाल गृह हैं। एक वे जो पंजीकृत तो हैं, मगर उनके यहां बच्चों के लिए सुविधा तक नहीं है। दूसरे वे जो पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे गृहों से बेहतर सुविधा की उम्मीद तक बेमानी है। बिहार का मामला सामने नहीं आया होता और केंद्र सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई होती तो ये बाल गृह आज भी बच्चों का शोषण कर रहे होते और हम-आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े बदरंग तस्वीर पर चौड़े हो रहे होते। इन बाल आश्रय गृहों की सच्चाई सामने आने के बाद सिर्फ राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ही नहीं समाज को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। किसी भी अच्छी या बुरी घटना का सीधा संबंध सबसे पहले समाज से होता है। सरकार व प्रशासन की भूमिका बाद में सामने आती है। अगर इस मसले पर समाज अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाया, तो आश्रय संचालकों को दोष देने से क्या फायदा? केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा और न ही यह बुराई समाप्त होगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बेसहारा बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रय स्थलों से उजागर हुए यौन-उत्पीड़न के मामलों से साफ है कि उनके संचालन में भ्रष्टाचार गहरे पैठ बनाए हुआ था। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चलने के बावजूद संबंधित सरकारी महकमों और उनके अधिकारियों को उनमें कुछ भी गलत होता नहीं दिखा। सवाल है कि अगर यह सोशल ऑडिट का काम नहीं हुआ होता तो क्या वहां वे गतिविधियां पहले की तरह चलती रहतीं? किसी गैरसरकारी संगठन के जरिए संचालित उन आश्रय स्थलों की निगरानी और जांच-पड़ताल क्या उन सरकारी महकमों का दायित्व नहीं है, जो उन संस्थाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं?

ट्रेनों में लफंगों से मिले मुक्ति

ट्रेन या बस में सफर के दौरान कई बार हमारा सामना ऐसे तथाकथित यात्रियों से हो जाता है, जो न सिर्फ बेसुरी आवाज में गाना गाकर पैसे वसूलते हैं, बल्कि सफर को मुश्किल भी बनाते हैं। ऐसे यात्रियों को रोकने के लिए ट्रेनों में सुरक्षा बन तैनात रहता जरूर है, मगर यात्रियों को कोई खास राहत नहीं मिल पाती। ट्रेनों में किन्नरों के प्रवेश को रोकने को लेकर रेलवे कई बार दावा कर चुका है, मगर धरातल पर सब शून्य है।

भारतीय नागरिकों को अपनी दिनचर्या में आए दिन ऐसी-ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे यह अहसास होता है कि सभी कायदे-कानून व पाबंदियां संभवतः कानून का पालन करने वाले शरीफ, सज्जन, मेहनतकश व ईमानदार लोगों के लिए ही हैं और यदि कोई शरीफ व्यक्ति किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में नियम व कानून से हटकर कोई कदम उठाता भी है तो प्रशासन व कानून उसे उसके किए की सजा देता ही है। परंतु ठीक इसके विपरीत ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे ही समाज में पलने वाले कई लुच्चे-लफंगे भिखारी वेशधारी तथा मवाली किस्म के लोग दिन-रात नियम और कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसे लोग शरीफ, सज्जन तथा कानून का पालन करने वालों के लिए सिरदर्द बनते हैं। उनकी सुरक्षा को भी चुनौती देते हैं। परंतु इन सबके बावजूद प्रशासन तथा कानून ऐसे लोगों की तरफ से अपना मुंह फेरे रहता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नियम-कानून का पालन करना क्या केवल सज्जन एवं शरीफ लोगों का ही फर्ज है? क्या वजह है कि कानून का पालन न करने वालों को तो कानून उल्लंघन की छूट दी जाती है जबकि एक शरीफ व्यक्ति उसी जुर्म में जुर्माने या जेल जाने तक की नौबत पर पहुंच जाता है।

उत्तर भारत में हम रेलगाड़ियों के माध्यम से कहीं भी चले जाएं आपको चलती ट्रेन में किन्नर वेशधारी, भिखारी या गाने बजाने वाले लोग जरूर मिलेंगे। यह लोग अपने निर्धारित रूट पर सुबह से शाम तक रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं तथा अनैच्छिक रूप से किसी भी यात्री के सिर पर खड़े होकर ढोल और डफली तक पीटने लगते हैं तथा गला फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति सो रहा है या उनका गाना नहीं सुनना चाहता। स्वयं को किन्नर बता कर रेल यात्रियों से ठगी करने वाले लोग तो कई बार किसी यात्री द्वारा पैसे न देने पर यात्री के मुंह पर तमाचा जड़ देते हैं। हमारी व्यवस्था के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती और अभिशाप है कि एक टिकटधारी शरीफ यात्री के गाल पर वह व्यक्ति तमाचा मारता है जिसने न तो कोई टिकट ले रखा है न ही उसके पास ट्रेन में भीख मांगने का अधिकार पत्र हासिल है।

ऐसे ही तमाम गेरुआ वस्त्रधारी लोग भी अपने भगवे लिबास को ही रेलवे का यात्रा पास मानकर पूरे देश में आते-जाते रहते हैं और न केवल सीटों पर कब्जा जमाए रहते हैं बल्कि प्रवेश व निकासी द्वार पर भी अड़े बैठे रहते हैं जिससे ट्रेन में चढ़ने एवं उतरने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार इन्हीं भगवा वस्त्रधारी भिखारियों को चलती ट्रेन में बिना किसी भय व लिहाज के खुल्लम खुला शराब पीते व सिगरेट का धुंआ उड़ाते भी देखा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत कोई भी जिम्मेदार, शरीफ नागरिक ऐसी हरकत नहीं कर सकता है और यदि कर भी दे तो पुलिस अथवा रेलवे अधिकारी उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करना तथा नाचना गाना, भीख मांगने जैसी बातें तो सुनने और देखने में आती रहती हैं। परंतु बसों में इस प्रकार का चलन लगभग न के बराबर था। मगर पिछले कुछ वर्षों से अब बसों में भी यह सिलसिला शुरू हो गया है। पहले बसों में किसी स्टैंड पर खड़ी बस में कुछ मेहनतकश लोग प्रवेश करते थे और यात्रियों को आकर्षित कर कोई न कोई सामान बेचने की कोशिश करते थे और बस के प्रस्थान करते समय ही वे बस से नीचे उतर जाते थे। परंतु अब तो ट्रेन की ही तर्ज पर बस में भी डफली, ढोलक तथा कान फोड़ू बेसुरा संगीत आदि सब कुछ सुनाई देने लगा है।

यदि हम अंबाला-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर बस से यात्रा करते हैं तो अंबाला से लेकर लालडू-डेराबस्सी-जीरकपुर व चंडीगढ़ आदि स्थानों पर कहीं न कहीं कोई न कोई नवयुवक बस पर सवार होता या फिर उतरता दिखाई दे जाएगा। कम आयु के यह बच्चे सरकारी बसों के कंडक्टर एवं ड्राइवर की ओर से मिलने वाली ढील का फायदा उठाकर एक स्टेशन से दूसरे व दूसरे से तीसरे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान वे न केवल अपने गला फाड़ गायन से यात्रियों को विचलित करते हैं बल्कि दान देकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले चंद लोग ऐसे लफंगों को कुछ पैसे देकर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। बसों में चढ़कर इस प्रकार पैसे मांगने वालों में अधिकांश बच्चे नशे की लत का शिकार होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी यात्री ने अवांछित रूप से लफंगों के चलती बस में चढ़ने पर आपत्ति की तो ड्राइवर ने उसी समय बस रोक कर उस लफंगे भिखारी को बस से नीचे भी उतार दिया, लेकिन विरोध नहीं किया तो सब कुछ पहले जैसा चलता रहता है।

इन्हीं बसों में कई बार किसी अनाथलाय आश्रम अथवा किसी भंडारा या फिर धार्मिक स्थान के नाम पर पैसा वसूली करने वाले लोग अपने हाथों में गुल्लक व रसीद बुक लेकर भी सवार हो जाते हैं। बसों में प्रवेश करने वाले इन सभी अनाधिकृत लोगों को यदि हम श्रेणी में भी बांटेंगे तो यही देखेंगे कि कोई सामग्री बेचने वाला या खाने-पीने की वस्तु बेचने वाला मेहनतकश मजदूर तो खड़ी बस में चढ़ता है और बस चलते ही उतर जाता है, जबकि चंदा वसूली करने वाले, भिखारी व अवांछित कान फाड़ गायक बेधड़क होकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की यात्रा बिना टिकट खरीदे करते हैं और यह हमारे देश का चमत्कार ही है कि ऐसे लोग सामान बेचने वाले मेहनतकश लोगों से भी ज्यादा पैसे मुफ्त में ठग कर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो नारियल गरी, कंघी या पानी बेचने वाला एक व्यक्ति अपनी मेहनत से दिनभर में तीन सौ से चार सौ रुपए तक कमाता है तो यह मवाली, भिखारी व मुफ्तखोर, लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर एक हजार रुपए से दो हजार रुपए तक बिना किसी पूंजी के कमा लेते हैं। उत्तर भारत में कई स्थानों पर रेलगाड़ियों में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो अपने साथ किसी युवती को रखते हैं। उसे अपनी बेटी या फिर बहन बताकर उसके विवाह और कन्यादान के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं।

यह शातिर दिमाग लोग यात्रियों को इन शब्दों में ब्लैक मेल करते हैं। वे कहते हैं कि-जैसे आपकी बेटी वैसे ही यह मेरी बेटी है लिहाजा इसके कन्यादान में अपनी बेटी समझकर सहयोग दीजिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार के कई पेशेवर लोग गत् 15-20 वर्षों से एक ही लड़की का हाथ पकड़कर उसके कन्यादान हेतु भीख मांग रहे हैं परंतु अब तक उस कथित बेटी की शादी ही नहीं की गई। इन लोगों के पास भी टिकट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार में दिसंबर की जबरदस्त ठंड में रात एक बजे के करीब बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रोते हुए प्रवेश किया और यह कहकर अपनी छाती पीटने लगा कि मेरे बेटे की लाश गेट पर पड़ी है और उसके पास संस्कार हेतु पैसे नहीं हैं। कई भावुक दानियों ने सौ-पचास रुपए की नोट उसे देनी शुरू कर दी। एक जागरूक युवा व्यक्ति ने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और कहा चलकर अपने बेटे की लाश दिखाओ। मैं उसका पूरा संस्कार स्वयं कराऊंगा। काफी आनाकानी के बाद वह बुजुर्ग हाथ जोड़ने लगा और अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगा। गोया देश में रेलगाड़ियों और बसों में इस प्रकार के यात्रियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि लफंगों को तो बेटिकट चलने की छूट है परंतु एक शरीफ, ईमानदार और मेहनतकश व्यक्ति को तो बाटिकट अर्थात टिकट खरीदकर ही चलना पड़ेगा। देश के शासनतंत्र को इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ताकि यात्रियों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सके। इस तरह के बेटिकट यात्री ही सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं।

निर्मल रानी
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

देश के बाल गृहों की जांच अब भी जारी है। अनियमितता पाए जाने पर उन्हें भी बंद किया जाएगा। बच्चों के अधिकार से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री

देशभर के बाल आश्रय गृहों को सिर्फ इसलिए मनमानी का अधिकार मिला क्योंकि उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं था। प्रशासनिक मशीनरी अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रही थी।

विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार

सत्यार्थ

वाशिंगटन का साहस

एक बार उत्तरी वर्जीनिया में कुछ युवक भ्रमण के लिए पहुंचे। घूमते-घूमते जब वे एक स्थान पर भोजन करने के लिए बैठे, तो उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह जोर-जोर से कह रही थी-मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। युवक भोजन छोड़कर उस ओर दौड़े, जिस ओर से आवाज आ रही थी। उस स्त्री का बच्चा नदी में गिर गया था और कोई भी व्यक्ति उसको निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस स्त्री ने कहा- आप मुझे इन संबंधियों से छुड़ा दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे को नदी से निकाल सकूं। ये न तो स्वयं कोई प्रयत्न कर रहे हैं और न ही मुझे कुछ करने दे रहे हैं। तभी उन में से एक युवक ने पलक झपकते ही कुछ निश्चय किया और कपड़े उतारकर नदी में कूद गया। वह एक अच्छा तैराक था और लहरों से जूझ रहा था। वह युवक जान हथेली पर रख बहते हुए बच्चे का पीछा कर रहा था, ताकि बच्चा उसकी पकड़ में आ जाए, पर लहरें बार-बार उसे दूर कर देतीं व बच्चे को उसके हाथ से छीनकर ऐसे ले जातीं, जैसे उन्होंने कसम खा रखी हो कि बच्चे को उस के हाथ नहीं आने देंगी। अंततः युवक बच्चे तक पहुंच ही गया व उसे नदी से बाहर निकाल लाया। बच्चे की मां अपलक नेत्रों से युवक को निहार रही थी। फिर वह ईश्वर का बारंबार आभार व्यक्त करने लगी। उसने कहा- तुम्हारे इस उपकार का बदला कोई भी और कभी भी नहीं चुका सकता। मेरे बच्चे के प्राण बचा कर तुमने मुझ पर जो उपकार किया है, उसका फल तुम्हें ईश्वर ही देंगे। मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूं कि तुम्हारी कीर्ति युगों-युगों तक फैले। बच्चे के लिए अपने प्राण की बाजी लगाने वाला यह युवक जार्ज वाशिंगटन था, जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना।

राधा नावीज

भारत में 26/11 जैसा एक और हमला छेड़ सकता है युद्धः अमेरिकी विशेषज्ञ

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी विद्वानों, पूर्व राजदूतों और अधिकारियों ने चेताया है कि अगर भारत पर 26/11 जैसा हमला दोबारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने सोमवार को 2008 के मुंबई हमलों की दसवीं बरसी से पहले यह बात कही। पाकिस्तान के आंतकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों के उस हमले में अमेरिकी नागरिकों समेत करीब 166 लोग मारे गए थे। पुलिस ने नौ आतंकियों को मार गिराया था जबकि अजमल कसाब को गिरफ्तार कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फांसी पर लटका दिया गया था।

मुंबई हमले को दस साल होने के बावजूद पाकिस्तान में इसके किसी भी संदिग्ध को अभी तक सजा नहीं मिली है, जो दिखाता है कि यह मामला कभी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रीडल ने कहा, ÷26/11 हमले के पीड़ितों को अब भी हमले के सरगनों और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ न्याय देखना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में ये नामुमकिन सा लगता है।÷

रिडेल का मानना है कि इस तरह के किसी दूसरे हमले का नतीजा दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और फिलहाल हडसन इंस्टिट्यूट में दक्षिण और मध्य एशिया के सीनियर फेलो और निदेशक हुसैन हक्कानी ने कहा कि अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट के चलते भारत में एक और आतंकी हमला होने पर हालात को कैसे काबू किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

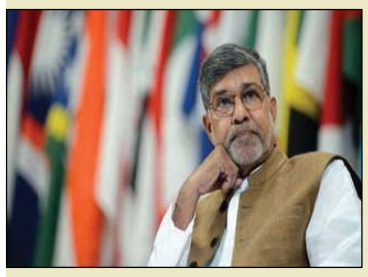

हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान को 26/11 हमलों के सरगनों के खिलाफ कार्रवाई का वादा निभाना चाहिए। हमलों के समय नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के निदेशक रहे अनीश गोयल ने कहा कि उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हमारी प्राथमिक चिंताओं में से एक थी, जिसमें हम रोकना चाहते थे।

गोयल ने बताया कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तुरंत कार्रवाई का काफी दबाव था। उस दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, विदेश मंत्री कोंडालीजा राइस ने ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए कई प्रयास किए थे जिनमें भारत पाकिस्तान और अमेरिका के कई सहयोगियों को फोन कॉल करना भी शामिल है। ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर उस तरह का एक और हमला हुआ तो इलाके में युद्ध की संभावनाएं तेजी से बढ़ जाएंगी। अधिकारी ने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती बरत रही है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक किया जाना भी शामिल है।

सार समाचार

कोलंबिया के कैरेबियाई द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप

बोगोटा। कैरेबियाई सागर में कोलंबिया के स्वामित्व वाले एक द्वीप पर शनिवार को 6.1 तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया हालांकि अधिकारियों ने बताया कि सूनामी की चेतावनी जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर में भूकंप की निगरानी करने वाली यूएस जियोलॉजिकल सर्विस (यूएसजीएस) के मुताबिक रविवार को तड़के तीन बजकर 40 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम (जीएमटी) पर कोलंबिया के पहाड़ के 32 किलोमीटर दक्षिणपूर्व में यह भूकंप दर्ज किया गया। कोलंबियाई भूगर्भ सेवा और यूएसजीएस दोनों ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहरा था। कोलंबियाई अधिकारियों ने कहा कि सैन एंड्रेस, प्रोविडेंशिया और सांता कातालीना नगरपालिकाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। यह द्वीप निकारागुआ के पूर्वी तट से करीब 220 किलोमीटर दूर स्थित हैं।कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने कहा कि देश की कैरेबियाई तटरेखा पर सूनामी की कोई चेतावनी नहीं है और इनसे किसी तरह के नुकसान की भी खबर नहीं है।

बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम उन्मूलन संभव है: कैलाश सत्यार्थी

न्यूयॉर्क। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम उन्मूलन संभव है और इसके लिए उन्होंने लोगों, विशेष रूप से दुनिया के युवाओं को गुलामी में जीने को मजबूर और यौन दुर्व्यवहार का सामना कर रहे बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में 'सहयोगी' बनने का आह्वान किया। सत्यार्थी ने बताया, ''बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है और दुनिया में अभी भी दासता अपने सबसे क्रूर रूपों में मौजूद है, लेकिन दासता और बाल श्रम उन्मूलन संभव है, यह हमारी पहुंच में है, इसलिए एक उम्मीद है।' बाल श्रम, बाल यौन शोषण और तस्करी से लड़ने के उनके लंबे प्रयासों पर केंद्रित यूट्यूब की मूल वृत्तचित्र 'द प्राइस ऑफ फ्री' 27 नवंबर को वैश्विक स्तर पर मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने जा रही है। इस फिल्म में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और उनकी टीम के बारे में दिखाया जाएगा कि कैसे वे दासता और उत्पीड़न झेल रहे मजबूर बच्चों को बचाने के लिए गुप्त और जोखिमभरे छापे मारते हैं, साथ ही लापता बच्चों को खोजने के लिए कैसे साहसपूर्ण कदम उठाते हैं। 90 मिनट लंबी इस फिल्म को 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, फिल्म ने 'यूएस डॉक्यूमेंट्री ग्रैंड ज्यूरी प्राइज' जीता था। सत्यार्थी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में वैश्विक प्रयासों से बाल मजदूरों की संख्या 26 करोड़ से कम होकर 15.2 करोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, 'इसे पूरा करना संभव है। हम सही मार्ग पर हैं,' उन्होंने कहा कि यह वृत्तचित्र बाल दासता को तेज गति से खत्म करने के प्रयासों में मदद करेगी।

ट्रंप को 2016 का राष्ट्रपति चुनाव जीताने में फेसबुक विज्ञापन रहे मददगार

लंदन (एजेंसी)।

फेसबुक पर मतदाताओं को लक्षित करके किए गए विज्ञापन अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी मददगार रहे. ये विज्ञापन उन मतदाताओं को ट्रंप का समर्थन करने के लिए राजी करने में सक्षम रहे जिन्होंने अपनी एक राय नहीं बनाई थी. इस तथ्य का पता एक अध्ययन से चला है.

स्पेन के चार्ल्स द्ददद्द यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड के शोधकर्ताओं के अनुसार ट्रंप की टीम ने 4 करोड़ 40 लाख डॉलर फेसबुक पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान खर्च किए और 175,000 विभिन्न तरक के विज्ञापन दिए. वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने चुनाव के दौरान 2 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च किए.

इन अभियानों के दौरान विभिन्न तथ्यों जैसे कि लिंग, स्थान और राजनीतिक झुकाव को देखते हुए फेसबुक यूजर्स के पास संदेश भेजे गए. इससे इस बात की संभावना बढ़ती है कि वैसे मतदाता जिन्होंने यह तय नहीं किया था कि वह अपना मत किस उम्मीदवार को देंगे, इससे उनके ट्रंप को वोट देने की संभावना पांच फीसदी अधिक थी. वहीं दूसरी तरफ परिणाम यह दर्शाते हैं कि क्लिंटन अपने संभावित और स्वाभाविक मतदाताओं को अपनी तरफ न तो खींचने में सक्षम हो पाईं और न ही इन मतदाताओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ा पाईं.

शोधकर्ताओं ने कहा, 'दुर्भाग्यवश यह दिखाने के लिए उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि यह रणनीति क्यों ट्रंप के लिए कारगार रही और क्लिंटन के लिए नहीं.'

वित्त मंत्री न्यूचिन से असंतुष्ट होने की खबरों का ट्रंप ने किया खंडन

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन की काम की सराहना करते हुये उस खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल की नियुक्ति को लेकर ट्रंप अपने वित्त मंत्री न्यूचिन से नाराज हैं। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, ÷मैं अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन के कामकाज से बहुत खुश हूं और गर्व महसूस करता हूं।÷ एक जर्नल ने ट्रंप के सलाहकारों का हवाला देते हुये बताया था कि ट्रंप ने चीन के खिलाफ दंडात्मक व्यापार कार्रवाई और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को लेकर न्यूचिन के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। मामले से जुड़े एक शख्स ने जर्नल से कहा कि एक चर्चा के दौरान किसी ने न्यूचिन के प्रदर्शन की सराहना की। इसके बाद ट्रंप ने शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का जिक्र किया और कहा, ÷यदि वह अच्छे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ?÷। ट्रंप ने न्यूचिन के बारे में आई रिपोर्ट को ÷फर्जी समाचार÷ करार दिया।

ताइवान : समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं, सुरक्षा मिलेगी

ताइपे (एजेंसी)।

ताइवान ने समलैंगिक विवाह को खारिज कर दिया है. मार्च 2017 में उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे यूनियनों के पक्ष में फैसला देने के बाद यह जनमत सर्वेक्षण आया है जिन्होंने संसद को कानूनों में संशोधन करने या नए कानून पास करने के लिए दो साल का समय दिया था. बीबीसी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे शनिवार का मतदान कानून को प्रभावित करेगा. सरकार ने पहले कहा था कि शनिवार को हुआ जनमत संग्रह न्यायालय के फैसले के लिए जरूरी बदलावों को लाने से प्रभावित नहीं होगा.

रूढ़िवादी समूहों ने पूछा कि क्या ताइवान के नागरिक संहिता में एक आदमी और एक महिला के बीच विवाह को एक यूनियन के रूप में परिभाषित करने को लेकर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए जबकि लेस्बियन, समलैंगिक,

बाइसेक्शुअल, और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) एक्टिविस्ट्स ने समान विवाह अधिकारों की मांग की थी.

प्रारंभिक परिणामों ने दर्शाया कि रूढ़िवादियों को भारी समर्थन मिला, जबकि समलैंगिक अधिकार वाले कार्यकर्ता विफल रहे. अधिकारियों को अब नागरिक संहिता में बदलाव किए बिना एक विशेष कानून पारित किए जाने की उम्मीद है. बीबीसी ने बताया कि अभियान चलाने वालों को डर है कि संभावित कानून कमजोर होगा.

ताइवानी मीडिया ने कहा कि एक संभावित परिणाम यह हो सकता है कि समलैंगिक जोड़ों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी लेकिन शादी करने की अनुमति नहीं है. एक संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को राष्ट्रपति साई इंग-वेन, जिन्होंने स्थानीय चुनावों में हार के बाद ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी की नेता पद को छोड़ दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) को महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा. राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं थे और हमने अपने सभी समर्थकों को निराश किया.'

ब्रेक्जिट समझौता : यूरोपीय संघ के 27 नेताओं ने दी मंजूरी, पीएम से नहीं की मुलाकात

ब्रसेल्स (एजेंसी)।

यूरोपीय संघ के सदस्यों ने रविवार को ऐतिहासिक ब्रेक्जिट समझौते को मंजूरी दे दी. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के बिना संगठन के 27 नेताओं ने समझौते का समर्थन करने के लिए मुलाकात की. यह एक तरह से ब्रिटेन की 29 मार्च को संगठन से बाहर होने की तैयारी है. ईयू परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्विटर पर लिखा, '' ईयू27 ने यूरोपीय संघ-ब्रिटेन के संबंधों के भविष्य पर राजनीतिक घोषणापत्र तथा निकलने का समझौते का समर्थन किया है. '' ब्रसेल्स में एक विशेष शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जीन-क्लाउड जुंकर ने कहा कि यह एक ÷दुखद दिन÷ था. वह ब्लॉक के कार्यकारी प्रमुख भी हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जैसे देश का यूरोपीय संघ को छोड़ते देखना खुशी या जश्न का मौका नहीं है. ब्लॉक की ओर से समझौते पर बातचीत करने वाले फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री मिशेल बार्नियर ने कहा ''हम साथी, सहयोगी और मित्र बने रहेंगे. '' ब्रिटेन अगले साल 29 मार्च को यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा, लेकिन 21 और महीनों के लिए उसके एकल बाजार में बना रहेगा.

करतारपुर कॉरिडोर: सीएम अमरिंदर ने ठुकराया पाकिस्तान का न्योता, मगर नवजोत सिद्धू जाने के लिए तैयार

चंडीगढ़ (एजेंसी)।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में आंतकवादी हमलों और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्याओं का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार करतारपुर कॉरीडोर की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में पाकिस्तान के बुलावे को अस्वीकार कर दिया है. मगर उनकी सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इस न्योते को स्वीकार कर विदेश मंत्रालय में अनुमति के लिए अर्जी दे दी है.

सीएम अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एक पत्र लिख कर कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है लेकिन उन्होंने आ पाने में असमर्थता जताई. उन्होंने कहा कि न्योता स्वीकार नहीं करने के दो कारण हैं, ''पहला कारण यह है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक मारे नहीं जाते या घायल नहीं होते. हालात सामान्य करने की राह पर बढ़ने की बजाए ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.''

गिनाए ये कारण: मुख्यमंत्री ने इनकार का दूसरा कारण गिनाते हुए दावा किया कि पकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में अपनी नापाक गतिविधियां शुरू कर दी हैं. उन्होंने दावा किया, ''मार्च 2017 से राज्य में आईएसआई के 19 मॉड्यूल को निष्क्रिय किया गया, 81 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 79 हथियार, पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बने एचजी-84 टाइप के अनेक ग्रेनेड और कुछ आईईडी बरामद किए गए हैं.''

तो पूरा हो जाएगा मेरा सपना: कैप्टन सिंह ने कहा, ''मैं उम्मीद करता हूं कि (पाकिस्तान के) प्रधानमंत्री इन हालात को समझेंगे....मेरे लिए इस ऐतिहासिक अवसर पर पाकिस्तान में मौजूद रहना संभव नहीं है. जबकि तथ्य यह है कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में शीश झुकाना मेरा सपना रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जब एक दिन हत्याएं और रंजिश समाप्त हो जाएंगी तो मेरा यह सपना भी पूरा हो जाएगा.''

उधर, अमरिंदर सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने के लिए कॉरिडोर निर्माण के शिलान्यास समारोह में पाकिस्तान की ओर से बुलाए जाने पर खुशी जताई है. पाक के न्योते पर सिद्धू ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार करते हुए खुशी हो रही है, मैंने इस ऐतिहासिक मौके पर शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय में अर्जी दी है, अच्छे काम खुद बोलते हैं और खुद रास्ता भी बना लेते हैं.

सुषमा स्वराज भी नहीं जाएंगी: उधर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी 28 नवंबर को होने वाले इस समारोह में शरीक होने में असमर्थता जता दी है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को लिखे अपने पत्र में सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव अभियान के चलते वह पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आएंगे.

श्रीलंका : राष्ट्रपति ने कहा, विक्रमसिंघे 'अत्यधिक भ्रष्ट', मैं उन्हें क्क्रू नहीं बनाउंगा

कोलंबो (एजेंसी)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने रविवार को फिर दोहराया कि वह चिर-प्रतिद्वंद्वी रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद पर पुनर्नियुक्त नहीं करेंगे. गौरतलब है कि श्रीलंका में एक महीने से अधिक समय से राजनीतिक संकट चल रहा है. विक्रमसिंघे की पार्टी का संसद में बहुमत है और सिरिसेना का, प्रधानमंत्री पद पर महिन्द्रा राजपक्षे को बिठाने का प्रयास विफल हो चुका है. विदेशी संवाददाताओं के साथ एक वार्ता के दौरान सिरिसेना का गला रूंध गया और उन्होंने विक्रमसिंघे पर 'अत्यधिक भ्रष्ट' होने का आरोप लगाया.

सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को 26 अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया था. विक्रमसिंघे की यूनाईटेड नेशनल पार्टी का हवाला देते हुये उन्होंने कहा, ''यहां तक कि अगर यूएनपी बहुमत में है तब भी मै उनसे रानिल विक्रमसिंघे को मेरे सामने लाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाउंगा.''

श्रीलंकाः राष्ट्रपति ने राजनीतिक संकट समाप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक की

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने पिछले महीने प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के अपने विवादास्पद फैसले से उत्पन्न राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक की. यह संकट तब पैदा हो गया था जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने अचानक घोषणा की थी उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर उनकी जगह महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है. सिरिसेना ने बाद में संसद भंग कर दी थी और मध्यावधि चुनाव का आदेश दिया था. संसद का कार्यकाल पूरा होने में करीब 20 महीने बाकी है.

आईएस ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, मार गिराए यूएस समर्थित 47 सैनिक

बेरूत (एजेंसी)।

सीरिया के पूर्वी हिस्से में पिछले दो दिन में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से किये गए हमलों में अमेरिका समर्थित 47 सैनिकों की मौत हो गयी. ब्रिटेन स्थित निगरानी संस्था ने शनिवार को यह जानकारी दी. सीरियन ऑब्जर्वेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स ने इससे पहले मरने वालों की संख्या 24 बतायी थी. निगरानी संस्था ने शनिवार को बताया कि जिहादियों ने तीन और हमले किये हैं.

'आईएस से काफी बड़ा खतरा है रूस'

ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल मार्क कार्लटन-स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अब रूस, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से काफी बड़ा खतरा बन चुका है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जून में जनरल स्टाफ प्रमुख के पद पर नियुक्त होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में जनरल कार्लटन-स्मिथ ने कहा कि निर्विवाद रूप से रूस अब अल कायदा और आईएस जैसे इस्लामी आतंकी समूहों से बड़ा खतरा बन चुका है.

उन्होंने कहा, 'रूस ने पश्चिमी अतिसंवेदनशीलता की छानबीन और शोषण करने के सुनियोजित प्रयास किए हैं, विशेषकर साइबर, अंतरिक्ष, समुद्र के भीतर युद्ध के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में.' कार्लटन-स्मिथ ने कहा, 'हम रूस द्वारा पैदा किए गए खतरे को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते और न ही इसे निर्विरोध छोड़ सकते हैं.'

54 वर्षीय पूर्व एसएएस कमांडर ने 11 सितंबर, 2001 आतंकी हमले के बाद मार गिराए गए आतंकी ओसामा बिन लादेन की तलाश का नेतृत्व किया था. साथ ही उन्होंने इराक और सीरिया में आईएस से मुकाबले के लिए अभियान में ब्रिटेन की भूमिका में सबसे आगे थे.

सूरत समेत गुजरात में 23 स्थलों पर विहिप करेगी धर्मसभा

सूरत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) में धर्म सभा आयोजित की है। विहिप ने अब गुजरात में आगामी दिनों में धर्म सभा का आयोजन किया है7 गुजरात में 23 स्थलों पर धर्म सभा आयोजित की जाएगी। जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, नडियाद, राजकोट, सोमनाथ, सूरत, गोधरा, दाहोद, भरुच, पोरबंदर, जामनगर, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, हि मतनगर, डीसा, वापी, सूरत ग्रामीण, भुज, पाटण, छोटाउदेपुर शामिल हैं। पहली धर्म सभा गांधीनगर में 2 दिसंबर को होगी। जबकि अहमदाबाद 9 दिसंबर को धर्म सभा का आयोजन किए जाने की खबर है। बता दें कि अयोध्या में आज धर्म सभा आयोजित की गई है। जिसमें साधु-संतों समेत बड़ी संख्या में राम सेवक शामिल हुए। धर्म सभा में विहिप के उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि अब हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं जानी चाहिए। राम जन्म भूमि का बंटवारा हमे मंजूर नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए हमें पूरी जमीन चाहिए।

जुना वाडज दशामा की मंदिर के सामने एएमसी द्वारा कच्चे-पक्के मकानों को नोटिस देने के बाद तोड़ दिए जाने से सनसनी मच गई।

सब जेल के कैदी ने ही विडियो वायरल किया

सुरेन्द्रनगर में अधिकारियों के हप्ता की पोल खुलने से सनसनी

पान मसाला-तंबाकू के २५ रुपये, साधारण मोबाइल के १० हजार रुपये अधिकारियों को देते होने का खुलासा

अहमदाबाद । सुरेन्द्रनगर राज्य की जेल में पोल खुल जाने की घटना सामने आने पर राज्य जेल प्रशासन में सनसनी मच गई। सुरेन्द्रनगर की सब जेल में कैदियों के झगड़ा हो ऐसी स्थिति का निर्माण सामने आया। सब जेल में हुई मारपीट में चार कैदी और १ पुलिसकर्मी घायल हुए है। इतना ही नहीं, सब जेल का एक विडियो खुद कैदी ने वायरल करके जेल में चल रही लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों के हप्ता लेने की सिस्टम का पर्दाफाश किया गया था। यह कैदी ने पान-मसाला, मोबाइल सहित की कोई भी चीजवस्तु लाना हो तो इसका हप्ता बना था और इतनी रकम जेल के अधिकारियों को चुकाने से यह चीजवस्तु आसानी से जेल में लाने देने की छूट दिए जाते होने की लापरवाही का पर्दाफाश किया गया था। जेल के कैदी द्वारा वायरल किए गए यह विडियो की वजह से सुरेन्द्रनगर सब जेल में सनसनी मच गई है। विशेष करके जेल प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय हो गये। यह पूरी घटना की उच्च स्तर पर पुलिस शासकों द्वारा इसे ध्यान में लिया गया है और आगामी दिनों में यह मामले में कार्रवाई होने की संभावना है। जेल में मोबाइल, पान-मसाला और भोजन जैसी सभी सुविधा पैसा चुकाने से मिलती होने की बात का खुलासा वायरल में किया गया है। वायरल विडियो में जेलर साधारण मोबाइल के १० हजार रुपये और एन्ड्रोइड मोबाइल के १५,००० रुपये और एक मसाला के २५ रुपये लिए जाते होने का कैदी ने आरोप लगाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि, जेल में कैदियों को शराब भी मिल जाता है। पैसे लेकर पुलिस ऐसी सुविधा देते होने का आरोप लगाया गया है। घटना की वजह से १०८ एम्ब्युलन्स भेजी गई थी, लेकिन १०८ को उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने वापस भेज देने का आरोप लगाया जा रहा है। आगे वायरल विडियो में कैदियों को चोटें आयी होने का भी मालूम पड़ रहा है। कैदियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती होने का विडियो में उल्लेख यह वायरल विडियो में कैदी में मौज-मस्ती-भजन करते सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एटीएस ने सुरेश को शुकलतीर्थ से गिरफ्तार किया

अजमेर ब्लास्ट केस में वांटेड आरोपी आखिर में गिरफ्तार

अजमेर ब्लास्ट केस में सुरेश नायर कई वर्षों से फरार था :अब आरोपी की कस्टडी एनआईए को सौपी जाएगी

अहमदाबाद। २००७ के अजमेर ब्लास्ट केस में फरार चल रहे आरोपी सुरेश दामोदर नायर की गुजरात एटीएस ने भरूच के शुकलतीर्थ से गिरफ्तार करने से सनसनी मच गई। अजमेर ब्लास्ट केस में सुरेश नायर कई वर्षों से वांटेड था और आखिर में गुज रात एटीएस की टीम ने इसे गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की।

उल्लेखनीय है कि, अजमेर दरगाह ब्लास्ट जिसकी जांच एनआई ने द्वारा चल रही है, इसमें आरोपी सुरेश दामोदर नायर वांटेड था। आरोपी सुरेश नायर मूल खेडा जिला के ठासरा की निवासी है और अजमेर दरगाह के ब्लास्ट में इसकी सक्रिय गतिविधि सामने आई थी, तब से वह फरार चल रहा था। गत ११.१०.२००७ को अजमेर दरगाह में एक बम रखा गया था, जिसका विस्फोट होने पर तीन लोगों की मौत हुई थी, जबकि अन्य १७ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गुज रात एटीएस के अधिकारियों को निश्चित जानकारी मिली थी कि, सुरेश नायर आगामी दिनों में भरूच के शुकलतीर्थ की मुलाकात लेंगे और इसी वजह से एटीएस की टीम ने गुप्तापूर्वक लंबे समय से शुकलतीर्थ की निगरानी कर रहे थे। इस दौरान सुरेश नायर वहां आते ही एटीएस के अधिकारियों को इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे आगे की पूछताछ करने के लिए अहमदाबाद लेकर आई थी। एटीएस की टीम द्वारा इसकी पूछताछ करने के बाद इसे आगामी दिनों में एनआई को सौंपा जाएगा। आरोपी सुरेश नायर पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एनआई ने द्वारा अभी तक शुरू की गई जांच में यह सच्चाई सामने आई थी कि, सुरेश नायर ने कथित रूप से बम का सामान दूसरे आरोपियों को सप्लाय कर रही थी और वह खुद भी अपराध की जगह पर संबंधित समय में मौजूद था। ट्रायल कोर्ट द्वारा अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में कई आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को मालसामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

सेंट जेवियर्स कॉलेज नवरंगपुरा से मेमनगर सेंट जेवियर्स लोयला तक ईसाई समाज के लोगों द्वारा विशेष रैली आयोजित की गई।

शेरों की मौत का सिलसिला जारी

सावरकुंडला रेन्ज में से और तीन बालशेर के शव मिले

गीर क्षेत्र में एक के बाद एक शेर की मौत का सिलसिला जारी : वन्य और शेरप्रेमी लोगों में नाराजगी फैल गई है

अहमदाबाद। अमरेली के सावरकुंडला रेन्ज में और दो बालशेर और धारी की पाणीया रेन्ज में एक मिलाकर दो दिन में कुल तीन बालशेर की मौत होने की जानकारी मिलने से सनसनी मच गई। वन विभाग और राज्य सरकार का सभी सुरक्षित और शेरों की सुरक्षा युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे होने के दावे के बीच और तीन बालशेर की मौत हुई थी। इस तरह, गीर क्षेत्र में एक के बाद एक शेर की मौत का सिलसिला जारी रहा है, जिसकी वजह से वन्य और शेरप्रेमी लोगों में नाराजगी फैल गई है। दूसरी तरफ, गीर में किसलिए शेर की मौत का सिलसिला रूकता नहीं है और एक के बाद एक शेर तथा बालशेर की मौत हो रही है फिर भी सरकार और वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे है यह सहित के कई प्रश्न उठाये जा रहे हैं। अमरेली जिला के सावरकुंडला की वडाल बीट क्षेत्र में और तीन बालशेर की मौत की जानकारी सामने आने पर वन्य और शेरप्रेमी में शोक की लहर फैल गई। विशेष करके शेरों की सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर अब शेरप्रेमी ने चिंता व्यक्त करके सरकार और वन विभाग सहित के शासकों के विरूद्ध गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ, यह विवाद के बीच वन विभाग के अधिकारियों ने दो बालशेर की मौत इनफाइट के कारण हुई होने का बचाव पेश किया गया था। हालांकि, शेरप्रेमी लोगों को वन विभाग का बचाव विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने अब पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई है। गीर और इसके आसपास के क्षेत्र में शेरों की मौत का सिलसिला जारी रहा है। यह दोनों बालशेर के शव गीर अभ्यारण्य में स्थित गीर-पूर्व वन विभाग के तहत आता धारी की पाणीया रेन्ज और सावरकुंडला रेन्ज से मिला है। वन विभाग ने बचाव पेश किया है कि, प्राथमिक दृष्टि से बालशेर की मौत इन्फाइट के कारण हुई हो ऐसा लग रहा है। यह बालशेर के शरीर पर वन्यजीव के चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह बालशेर का शव धारी की पाणीया रेन्ज की चांचाई राउन्ड में स्थित भेराला बीट से मिली है।

सी प्लेन के लिए अब वॉटर एयरोड्राम बनाया जाएगा

अहमदाबाद। विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में राजपीपला सहित तीन स्थलों पर नये एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करने में और टूरिजम को और प्रोत्साहन देने के तहत अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रॉजेक्ट सी प्लेन के लिए नर्मदा बांध में वॉटर एयरोड्राम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कवायद शुरू की गई है। जिसमें वडोदरा एयरपोर्ट के डायरेक्टर चरणसिंह की मेन्टर के तौर पर नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार के टूरिजम विभाग के सचिव एसजे. हैदर के अनुसार, राज्य में अन्य चार जगह पर वॉटर एयरोड्राम बनाने के लिए आयोजन किया जा रहा है यह योजना से विभिन्न स्थलों की कनेक्टिविटी और टूरिजम को प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात में सी प्लेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रॉजेक्ट है। सूरत में हाल में तापी नदी में इस बारे में संभावना जांच की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवासियों की भीड़ देखकर राजपीपला में रनवे और एयरपोर्ट के लिए फिलहाल में घोषणा की गई थी, अब सरदार सरोवर बांध में सी प्लेन कनेक्टिविटी के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्लेन पानी में उतरे या टेक ऑफ करे इसके लिए निकट में एयरोड्राम जरूरी होता है। सरदार सरोवर के पास कहां यह स्थल उचित है, इस मामले में प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके वडोदरा एयरपोर्ट डायरेक्टर को देना होगा। राज्य सरकार के टूरिजम विभाग के सचिव के बताये अनुसार राज्य में चार स्थल आईडेन्टिफाय हुए हैं। साबरमती नदी, धरोई बांध और शत्रुंजय बांध में खुला पानी में वॉटर एयरोड्राम बनाने के लिए आयोजन है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)